

सी.पी.एस.मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के चलते मुख्य संसदीय सचिवों के पदों से हटाये गए कांग्रेस के सभी 6 विधायकों की सदस्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार की एस.एल.पी. पर आज ये फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार फिर से सीपीएस की नियुक्ति नहीं कर सकती लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी और उनके खिलाफ फिलहाल अयोग्यता का मामला नहीं चलेगा। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ विधायकों की अयोग्यता रद्द करने पर ही रोक लगाई है जबकि मुख्य संसदीय सचिवों को पद से हटाए जाने के हाई कोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों से संबंधित हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2006 का कानून रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को काफी राहत मिली है।

हर्ष वर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा है कि जनसेवा, जन समस्याओं का समाधान और पिछड़े क्षेत्रों व वर्गों का उत्थान कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्ष वर्धन चौहान आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया। हर्ष वर्धन चौहान ने अधिकारियों को शेष समस्याओं का निर्धारित समय के भीतर समाधान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा रखी गई मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

यादविंदर गोमा

आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गोमा आज जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र के पपरोला से आलमपुर को जोड़ने वाले पुल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है और इस दिशा में गंभीरता से प्रयास

किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पुल का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस पुल के निर्माण पर साढ़े आठ करोड़ रूपए खर्च होंगे।

संजय रत्न

विधायक संजय रत्न ने अधिकारियों से कहा है कि वे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद और पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। संजय रत्न ने आज धर्मशाला में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सभी पंचायतों में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बोर्ड और जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के 9687 नये मामलों को मंजूरी दी गई।

बैडमिंटन

शिमला जिला स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 6 और 7 दिसंबर को शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तुर्की और महासचिव सुमित धौटा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रतियोगिता 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 वर्ष आयु वर्ग में होगी। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर पर शिमला जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने सभी मास्टर बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

कर्ण नंदा

भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कर्ण नंदा ने मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार द्वारा एक मीडिया कर्मी के खिलाफ की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कांग्रेस को मीडिया विरोधी करार दिया और कहा कि वह सच से भागने का काम करती है। भाजपा प्रवक्ता विवेक शर्मा ने भी इस घटना की निंदा की है।

संजय अवस्थी

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खासकर कमजोर वर्गों की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। संजय अवस्थी अर्की

विधानसभा क्षेत्र की जघून पंचायत घर के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।